



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2002/चैत्र 12, 1924

No. 66]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2002/CHAITRA 12, 1924

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2002

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनिधान) (संशोधन) विनियम, 2002

फा.सं. आईआरडीए/रेग्यु/03/2002.— प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 27क, 27ख, 27घ और 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनिधान) विनियम, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनिधान) (संशोधन) विनियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 4 के पश्चात् टिप्पण 7, जो दोनों, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के विनियम 3 और विनियम 4 को लागू होता है, निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है :-

7. “किसी रजिस्ट्रीकृत स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध साधारण अंशों में विनिधान सक्रिय रूप में व्यापार किए जाने वाले और तरल लिखतों, अर्थात् समय-समय पर भारतीय प्रतिभूति एक्सचेंज बोर्ड द्वारा जारी किए गए पारस्परिक निधियों को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार अल्प रूप में व्यापार किए जाने वाले के रूप में वर्गीकृत से भिन्न, साधारण शेयरों में किए जाने चाहिए।”

3. विनियम 5 का निम्नलिखित रूप में संशोधन किया जाएगा :

“ 5. अरक्षण/प्रज्ञापूर्ण मानक

अधिनियम की धारा 27क और 27ख में अन्तर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक बीमाकर्ता निम्नलिखित अरक्षण मानकों पर आधारित अपने विनिधानों को सीमित करेगा :-

विनिधान/अरक्षण	विनिधानकर्ता कंपनी के लिए सीमा	उस समस्त समूह के लिए सीमा, जिसकी विनिधाता कंपनी अंग है।	उस उद्योग क्षेत्र के लिए सीमा, जिसकी विनिधाता कंपनी अंग है।
(क) कंपनी के साधारण/अधिमानी शेयरों में सभी विनिधान	भारतीय बीमा कंपनियों की दशा में : किसी भी समय अरक्षण, विनिधाता कंपनी की अभिदत्त शेयर पूंजी, खुली आरक्षितियों और डिबेंचरों/बंधपत्रों के 10 प्रतिशत से या गैर-जीवन बीमाकर्ता की दशा में बीमाकर्ताओं की कुल आस्तियों के 10 प्रतिशत और जीवन बीमाकर्ताओं की दशा में नियंत्रित निधियों के 10 प्रतिशत से, इनमें से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी।	किसी भी समय अरक्षण, उन सभी समूह कंपनियों की, जिनमें विनिधान, जिनके अन्तर्गत विधायी विनिधान भी हैं, बीमाकर्ता द्वारा किए गए हैं या किए जाने प्रस्तावित हैं, सकल अभिदत्त शेयर पूंजी, खुली आरक्षितियों और डिबेंचरों के 10 प्रतिशत से या गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की दशा में कुल आस्तियों के 10 प्रतिशत और जीवन बीमाकर्ताओं की दशा में नियंत्रित निधियों के 10 प्रतिशत से, इनमें से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी।	बीमाकर्ता द्वारा किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में अविनिधान, संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में उसके कुल विनिधान अरक्षण के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। (औद्योगिक क्षेत्र का वर्गीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था अनुश्रवण केन्द्र (सी एम आई ई) द्वारा किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार किया जाएगा।)

1. बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार अरक्षण सीमाओं के अधीन रहते हुए, शेयरों में विनिधान, जिसके अन्तर्गत अधिमानी शेयर भी हैं, डिबेंचरों के संपरिवर्तनीय भाग के शेयरों में विनिधान सारणी में ऊपर उल्लिखित अरक्षण मानकों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। एक ऐसी ही 50 प्रतिशत के अरक्षण मानकों की सीमा स्थावर संपत्ति में विनिधान को भी लागू होगी।

2. ऊपर सारणी में उल्लिखित आरक्षण सीमाओं के अधीन रहते हुए, कोई भी बीमाकर्ता, संप्रवर्तकों के समूहों की अंग कंपनियों में जीवन बीमाकर्ता की दशा में अपनी नियंत्रित निधियों के सकल के 5 प्रतिशत से या गैर-जीवन बीमाकर्ता की दशा में अपनी आस्तियों के सकल के 5 प्रतिशत से अधिक का विनिधान नहीं करेगा। इस विनियम के प्रयोजनों के लिए “समूह” का वही अर्थ होगा जो उसका एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में उसका है। इस प्रवर्ग में सभी विनिधान विनिर्दिष्टः प्राधिकरण को निर्देशित किए जाएंगे।

3. गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की दशा में कुल आस्तियों की 10 प्रतिशत की और जीवन बीमाकर्ताओं की दशा में नियंत्रित निधि की 10 प्रतिशत की प्रतिशतता को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के अधीन रहते हुए, प्रत्येक मामले में 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।”

4. विद्यमान बीमाकर्ताओं की दशा में :- भारतीय बीमा कंपनियों को लागू ऊपर उल्लिखित सीमाएं निम्नानुसार उपांतरित हो जाएंगी :-

(क) किसी भी समय अरक्षण, विनिधाता कंपनी की अभिदत्त शेयर पूंजी, खुली आरक्षितियों और डिबेंचरों/बंधपत्रों के 20 प्रतिशत से अथवा जीवन बीमा की नियंत्रित निधियों के 5 प्रतिशत से या कुल आस्तियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(ख) औद्योगिक क्षेत्र के लिए अरक्षण के संबंध में विहित सीमा, वित्तीय संस्थाओं में विनिधानों की दशा में 20 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।

एन. रंगाचारी, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन-III/IV/असाधारण/61/02]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March, 2002

Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) (Amendment) Regulations, 2002

F.No. IRDA/Reg./03/2002.—In exercise of the powers conferred by sections 27A, 27B, 27D and 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, namely :—

- 1 (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) (Amendment) Regulations, 2002.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2 Note 7 after Regulation 4 which is applicable to both Regulation 3 and Regulation 4 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) (Amendment) Regulations, 2001 is being substituted by the following: -

7. "Investments in equity shares listed on a registered stock exchange should be made in actively traded and liquid instruments viz. equity shares other than those classified as thinly traded as per guidelines governing Mutual Funds issued by SEBI from time to time."
- 3 Regulation 5 shall be amended to read as follows: -

" 5. EXPOSURE/ PRUDENTIAL NORMS

Without prejudice to anything contained in sections 27A and 27B of the Act, every insurer shall limit his investments based on the following exposure norms:

<i>Type of Investment</i>	<i>Limit for Investee Company</i>	<i>Limit for the entire group to which the Investee Company belongs</i>	<i>Limit for the Industry Sector to which the Investee Company belongs</i>
(a) All investments in Equity / Preference Shares of the Company (b) Debentures (Convertible / partly convertible/non-convertible) (c) Short/ Medium/ Long term loans (d) Any other permitted investments as per the Act/Regulation	In the case of Indian Insurance Companies: Exposure at any point of time not to exceed 10% of the subscribed share capital, free reserves and debentures/ bonds of the investee company or the 10% of the Insurer's total assets in case of non-life insurers and 10% of the Controlled funds in case of Life insurers, whichever is less.	Exposure at any point of time not to exceed 10% of the aggregate subscribed share capital, free reserves and debentures of all the group companies in which investments including investments under considerations, have been or proposed to be made by the insurer or the 10% of the total assets in case of Non-Life Insurers and 10% of the Controlled Funds in case of Life Insurers whichever is less.	Investment by the insurer in any industrial sector would not exceed 10% of its total investment exposure to the industrial sector as a whole. (Classification of Industrial sector to be done on the lines of classification in Industries done by CMIE (Centre for Monitoring Indian Economy))

Notes

1. Subject to exposure limits as per Insurance Act, 1938, investment in equity including preference shares, investment in equity convertible part of debentures should not exceed 50% of the above exposure norms as mentioned in the table. A similar 50% of exposure norms limit would also apply to investment in immovable property.
2. Subject to exposure limits mentioned in the table above, an Insurer shall not have investments of more than 5% in aggregate of its Controlled funds in the case of a life insurer or 5% in aggregate of its assets in the case

of non-life insurer in the companies belonging to the promoters' groups. For the purposes of this regulation "group" will have the same meaning as in the MRTP Act, 1969. All investments in this category would specifically be referred to the Authority.

3. The percentage of 10% of the total assets in the case of Non-Life insurers and 10% of the Controlled Fund in case of Life insurers can be raised to 15% in each case subject to specific approval of IRDA."
4. In the case of existing insurers: The limits mentioned above as applicable to the Indian Insurance Companies, shall stand modified as under:-
 - a) exposure at any point of time not to exceed 20% of the subscribed share capital, free reserves and debentures/ bonds of the investee company or 5% of the Controlled funds of the life insurer or 10% of the general insurers total assets.
 - b) The limit prescribed in respect of exposure to the industrial sector shall stand increased to 20% in the case of investments in Financial Institutions.

N. RANGACHARY, Chairman

[No. ADVT-III/IV/Exty./61/02]